उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 2 | 16-31 जनवरी 2022 | ₹ 20/-

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों के घेरे में

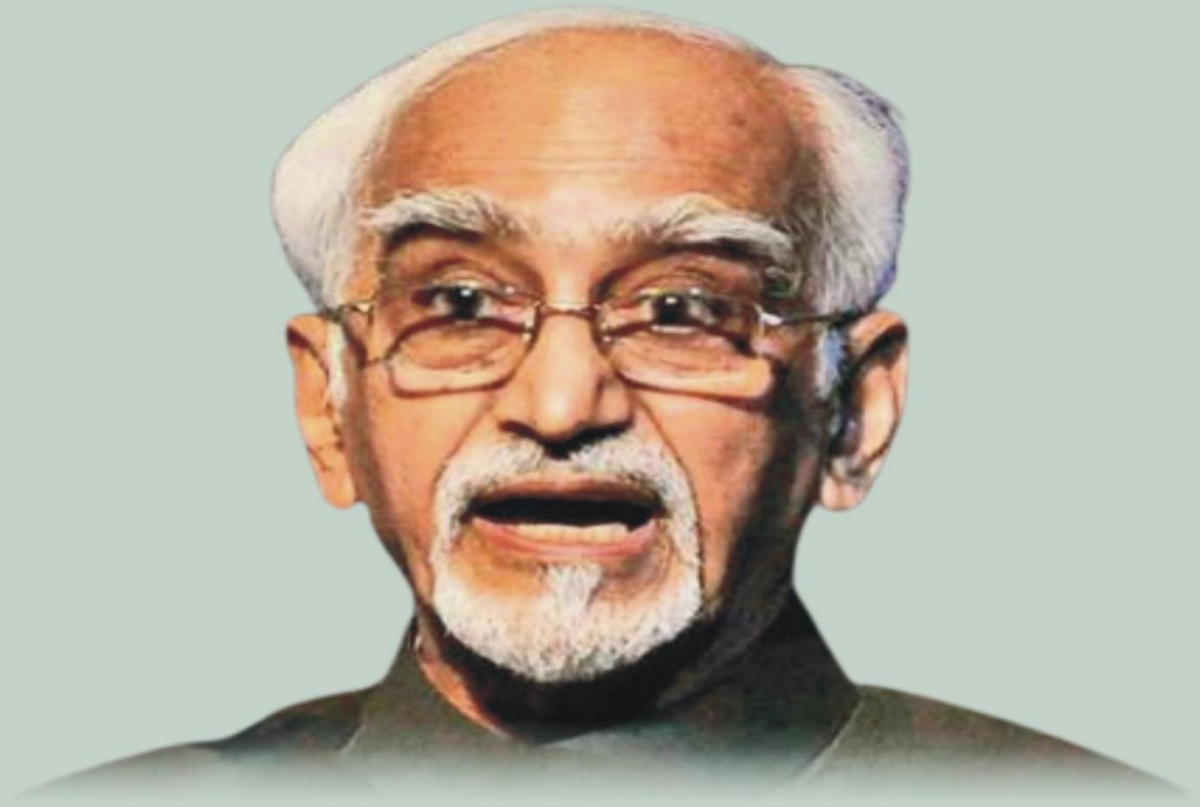

- हिंदू युवक की हत्या के मामले में विवादित मौलाना गिरफ्तार
- रूसी हमले की आशंका से यूक्रेन में तनाव
- संयुक्त अरब अमीरात पर हूती विद्रोहियों का हमला
- दारूल उलूम देवबंद का विवादित फतवा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों के घेरे में 04
हिंदू युवक की हत्या के मामले में विवादित मौलाना गिरफ्तार 07
दिल्ली के कब्रिस्तानों में दफन के लिए जगह की कमी 10
भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित 11
दरगाह की पूर्व प्रबंध समिति पर करोड़ों के घोटाले का आरोप 12

विश्व

रूसी हमले की आशंका से यूक्रेन में तनाव 14
पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद 16
तालिबान द्वारा प्रेस कांफ्रेंस के आयोजन पर प्रतिबंध 17
फिलीपींस भारत से मिसाइल प्रणाली खरीदेगा 18
सिंगापुर में पैगम्बर के विवादित कार्टून पर प्रतिबंध 18

पश्चिम एशिया

संयुक्त अरब अमीरात पर हूती विद्रोहियों का हमला 19
सऊदी अरब और इंडोनेशिया से राजनयिक संबंध बनाएगा इजरायल 21
सऊदी अरब में महलों को होटलों में बदलने की योजना 22
सूडान में जनरल बुरहान का नया मंत्रिमंडल 23
ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में पांच इजरायली गिरफ्तार 24

अन्य

हिंदुस्तानी दवाखाना का नाम बदलने पर विवाद 25
दारूल उलूम देवबंद का विवादित फतवा 25
शरई अदालत का उद्घाटन 26
मुनव्वर राना हैं परेशान 26
गैरमुसलमानों में इस्लाम का प्रचार 27
नेपाल की राष्ट्रीय सभा में मुस्लिम सदस्य मनोनीत 27
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वृद्ध व्यक्ति से मांगी माफी 27

सारांश

मुस्लिम समाज के एक वर्ग को इस्लाम और रसूल के नाम पर भड़काने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है। उनमें जिस नफरत व हिंसा का माहौल पैदा किया जा रहा है उसने गुजरात में एक 27 वर्षीय युवक किशन भरवाड की बलि ले ली। कहा जाता है कि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। इससे पहले ही वह अपनी पोस्ट को डिलीट करके माफी मांग चुका था। यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार एक मौलाना अयूब जावरवाला ने मुसलमानों को किशन के खिलाफ भड़काया। उसने इस बात पर जोर दिया कि रसूल और इस्लाम के दुश्मन को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। राजकोट में रहने वाले दो व्यक्तियों ने एक पिस्तौल और कुछ कारतूसों का प्रबंध किया और उसे लाकर मौलाना अयूब को सौंप दिया। मौलाना ने एक साजिश रची और यह पिस्तौल दो शार्प शूटरों को सौंपकर उन्हें यह निर्देश दिया कि इस्लाम के दुश्मन को हर कीमत पर खत्म किया जाए। इस सारी साजिश से बेखबर किशन जब किसी काम से सड़क पर निकला तो मोटरसाइकिल सवार इन दोनों व्यक्तियों ने उसे गोली से उड़ा दिया। इस घटना के खिलाफ राज्य भर में जनाक्रोश भड़क उठा। अनेक स्थानों पर हड़ताल और उग्र प्रदर्शनों में हत्यारों का पता लगाने और उन्हं गिरफ्तार करने की मांग की गई। गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच का जिम्मा एटीएस को सौंप दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि किशन भरवाड की हत्या की साजिश अहमदाबाद की जमालपुर स्थित एक मस्जिद में रची गई थी। पूछताछ के दौरान हत्यारों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें दिल्ली में रहने वाले एक मौलाना कमर गनी उस्मानी ने इस्लाम के दुश्मनों की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बाद में गुजरात पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया।

जहां तक उस्मानी का संबंध है गत कई महीनों से वह इस्लाम, रसूल और मुसलमानों के नाम पर जहर फैला रहा है। यह कथित मौलाना बरेलवी संप्रदाय से संबंधित है और अमेठी की एक दरगाह का सज्जादानशीन होने का दावा करता है। मगर पिछले कुछ वर्षों से वह दिल्ली के ओखला क्षेत्र में रह रहा है और उसने एक कट्टरपंथी संगठन 'तहरीक फरोग-ए-इस्लाम' बना रखा है। त्रिपुरा में हुए दंगों में भी इसने अपने तीन साथियों के साथ वहां पर सांप्रदायिकता की ज्वाला को भड़काने का प्रयास किया था, जिस पर त्रिपुरा पुलिस ने यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया था। त्रिपुरा की अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया था मगर एक कट्टरपंथी मुस्लिम वकील महमूद पराचा ने कानूनी दांव-पेंच का सहारा लेकर उच्च अदालत से उसको जमानत पर रिहा करवा लिया।

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और कांग्रेसी नेता मोहम्मद हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। अमेरिका स्थित इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और उनके खिलाफ असहिष्णुता का वातावरण बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि मुसलमानों को भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं मोदी सरकार उनका हनन कर रही है। कहा जाता है कि इस गोष्ठी के आयोजकों का संबंध पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से है और उसके इशारे पर ही भारत को विश्व भर में बदनाम करने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी वक्ता मोदी सरकार की आलोचना करते रहे।

राष्ट्रीय

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों के घेरे में

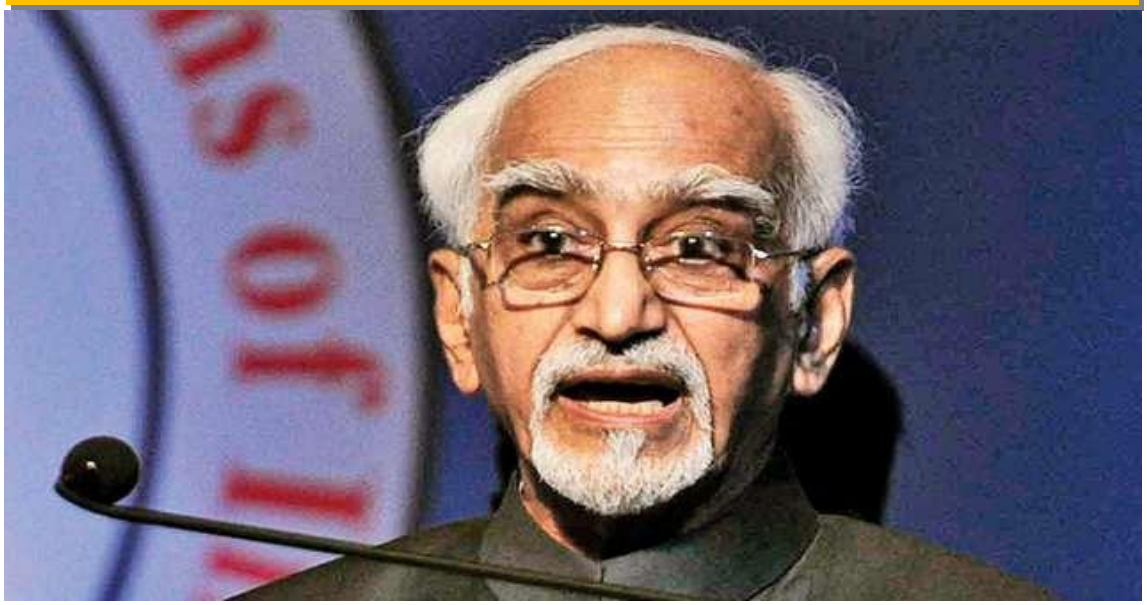

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक अमेरिकी संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लेते हुए मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। कहा जाता है कि जिस संगठन ने यह आयोजन किया था उसके पाकिस्तान के गुप्तचर संगठन आईएसआई से गहरे संबंध हैं। समाचारपत्रों के अनुसार इस आयोजन में भारत सरकार के खिलाफ खुलकर जहर उगला गया है।

इंकलाब (28 जनवरी) के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित एक वर्चुअल गोष्ठी में भाग लेते हुए देश में लोकतंत्र की बिगड़ती हुई हालत पर चिंता प्रकट करते हुए यह आरोप लगाया है कि देश अपने संविधान से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में हमने अपने देश में ऐसे रूझानों को उभरते देखा है जो कि पहले देश में स्थापित नागरिक राष्ट्रवाद को नजरअंदाज करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना को लाद रहे हैं। उन्होंने देश में 20 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही में बहुसंख्यक संप्रदाय को जो चुनाव में भारी बहुमत मिला है उसकी आड़ लेकर वे राजनीति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया जाए और उनमें असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे रूझान को राजनीतिक और कानूनी तौर पर चुनौती देने की आवश्यकता है।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस वर्चुअल परिचर्चा के प्रबंधकों में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, जेनोसाइड वाच, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स और न्यूयॉर्क स्टेट

काउंसिल ऑफ चर्चेज आदि संगठन भी शामिल थे। इस चर्चा में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत के अभियान, आतंकवाद निरोधक कानून और यूएपीए आदि के बारे में भी चर्चा हुई। समाचारपत्रों में यह भी आरोप लगाया गया था कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से गहरे संबंध हैं। मगर काउंसिल ने इस आरोप का खंडन किया है। उनका दावा है कि वह अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संरक्षण का संगठन है। इस वर्चुअल चर्चा में बंगलुरु के आर्कबिशप पीटर मचाडो ने भी भाग लिया था। उन्होंने खासतौर पर कर्नाटक के धर्मांतरण विरोधी कानून को अपना निशाना बनाया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अमेरिकी आयोग के प्रमुख ने इस चर्चा में भाग लेते हुए इस बात पर खेद प्रकट किया था कि हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। उनका कहना था कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार हिंदू राष्ट्र के अपने दृष्टिकोण को कानूनों द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों पर थोप रही है। जो कि देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित और आदिवासियों के खिलाफ हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी के सिनेटर एड माक ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का प्रयास कर रही है उससे वे काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर पाबंदी और नागरिकों से संबंधित बनाए गए हाल के कानून भारत के सेक्युलर संविधान और लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है। जब बुनियादी नागरिक अधिकारों का हनन हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना अमेरिका का कर्तव्य है और यह बात खास तौर पर उस समय महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब इस तरह की घटनाएं भारत में घटित हों। बुल्ली बाई ऐप का निशाना बनने वाली मुस्लिम महिला अमोना कौसर ने भी इसमें भाग लेते हुए कहा कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ यह अभियान भारत सरकार के संरक्षण में चल रहा है। मॉरीशस की पूर्व राष्ट्रपति अमीना गुरीब-फकीम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक अनुच्छेद मौजूद हैं। मगर उसके बावजूद समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार वहां पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इस राष्ट्र विरोधी बयान की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है और उसे अस्वीकार्य करार दिया है।

कौमी तंजीम (28 जनवरी) के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अंसारी का रवैया उस समय भी विवादित था जब वे अपने पद पर थे और इसके लिए देश ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। ऐसे में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के कार्यक्रम के संबोधन के दौरान उनका दिया गया हालिया बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और विदेश में उनका रूख बेहद शर्मनाक है। अंसारी का यह बयान कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बेहद खेदजनक है। एक विदेशी प्लेटफॉर्म पर व्यक्त की गई उनकी बयानबाजी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। देश उनकी धारणा को रद्द कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इससे पूर्व भी अंसारी जो बयान देते रहे हैं उसके कारण पूरे देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। देश ने उन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया था मगर उन्होंने वंदे मातरम् बोलने पर भी आपत्ति जताई थी।

सालार (28 जनवरी) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद ने अंसारी पर आरोप लगाया है कि वे देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्विट किया है कि हामिद अंसारी जैसे लोग संवैधानिक पदों से हटते ही सीधे नीचे क्यों गिर जाते हैं? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैस कट्टरपंथी संगठनों तक पहुंचते ही उनके अंदर का जिहादी इस्लाम क्यों जाग जाता है? भाजपा आईटी सेल के संयोजक अमित मालवोय ने भी अपने ट्विट में कहा है कि सोनिया गांधी के प्यारे और पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी ने भारत विरोधी तत्वों के साथ जानबूझकर देश को बदनाम करने के लिए मंच साझा किया है। जिस संगठन ने इस गोष्ठी का आयोजन किया था उसका संबंध कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से है।

इंकलाब (29 जनवरी) ने अंसारी का परोक्ष रूप से समर्थन करते हुए कहा है कि वास्तविक समस्या यह है कि हमारी सरकार को मुसलमानों पर होने वाली ज्यादतियों या उनके खिलाफ होने वाले शरारती प्रचार से बदनामी का कोई डर नहीं है। मगर देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वे विश्व में देश की छवि को धुमिल बनाने के प्रयासों को तुरूप के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे अपनी समस्याओं के साथ-साथ राष्ट्रीय समस्याओं के मुद्दों को भी उठाएं। अगर हम राष्ट्रीय समस्याओं पर बोलेंगे तो सरकार के लिए अपना दामन बचाना आसान नहीं होगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 जनवरी) ने अपने संपादकीय में हामिद अंसारी के बयान की निंदा करने वालों की आलोचना की है और कहा है कि एक विशेष विचारधारा के लोग और गोदी मीडिया अंसारी के खिलाफ इसलिए हंगामा करते हैं क्योंकि वे अधिकार की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में जुबान खोलते हैं। उनके बयान पर जो हंगामा हो रहा है उसकी आलोचना करते हुए समाचारपत्र ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ने बेबाकी से जो सच्ची बात कही है वह भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को हजम नहीं हो पा रही है।

टिप्पणी: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी प्रारंभ से ही विवादों में रहे हैं। उन पर यह आरोप लगता रहता है कि वे वैचारिक दृष्टि से एक कट्टर मुसलमान हैं। उनका जन्म 1937 में कोलकाता में हुआ था और उनकी शिक्षा-दीक्षा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। 1961 में वे भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और एक दर्जन से अधिक देशों में वे भारत के राजदूत भी रहे। 1984 में उन्हें पद्म सम्मान दिया गया। 2000-2004 तक व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। 2007 में कांग्रेस ने उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में उतारा और वे जीत गए। 2012 में उनके कार्यकाल में पांच वर्षों की वृद्धि की गई। उपराष्ट्रपति पद के विदाई समारोह में अंसारी ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाता है कि 30 दिसंबर 2011 को संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था और अन्ना हजारे आंदोलन के कारण लोकपाल विधेयक पर गरमा-गरम बहस हो रही थी। आधी रात के बाद अंसारी ने मतदान करवाने की बजाय अचानक सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। तब यह आरोप लगाया गया कि अंसारी ने यह कदम कांग्रेस सरकार को हार से बचाने के लिए उठाया था।

भारत की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी रॉ के कुछ पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि जब हामिद अंसारी ईरान में भारतीय राजदूत थे तो उन्होंन वहां की सरकार और वहां की गुप्तचर एजेंसी को अति गोपनीय सूचनाएं लीक करके रॉ

के एक महत्त्वपूर्ण ऑपरेशन में पलीता लगा दिया था। रॉ के एक अधिकारी संदीप कपूर को ईरान में वहां की गुप्तचर एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत हामिद अंसारी को यह निर्देश दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके कपूर को रिहा करवाने का प्रयास करें। मगर नई दिल्ली के इस निर्देश को नजरअंदाज करते हुए अंसारी ने भारत सरकार को यह झूठी रिपोर्ट दी कि संदीप कपूर लापता हैं और वे ईरान सरकार की हिरासत में नहीं हैं। इन अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि रॉ को यह सूचना मिली थी कि कुछ कश्मीरी आतंकवादियों को ईरान के एक नगर कोम में अस्त्र-शस्त्र चलाने का गुप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। मगर यह सूचना अंसारी ने ईरान सरकार को लीक कर दी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। मगर 2015 में भारत सरकार ने जब पहला योग दिवस मनाया तो उस कार्यक्रम से उपराष्ट्रपति गायब थे। उसी वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय ध्वज को अंसारी द्वारा सलामी न दिए जाने का भी मामला चर्चा में आया। ग्रेटर नोएडा में जब एक व्यक्ति अखलाक की हत्या की गई तो अंसारी ने केंद्र सरकार पर मुसमलानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। तीन वर्ष पूर्व जब सर्वोच्च न्यायालय ने सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पूर्व जब राष्ट्र गान अनिवार्य किया था तो मद्रास उच्च न्यायालय ने वंदे मातरम् को लेकर एक फैसला दिया था। इस पर भी टिप्पणी करते हुए अंसारी ने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। 2018 में जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के चित्र लगाने पर विवाद खड़ा हुआ तो अंसारी ने जिन्ना के चित्र को लगाने का समर्थन किया था। 2018 में ही उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा देश के प्रत्येक जिले में शरिया अदालतों को स्थापित करने का भी समर्थन किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ का वे खुलेआम समर्थन करते रहे हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात क स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह शिकायत की थी कि देश के मुसलमानों को मोदी सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है और उन्हें विकास की योजना से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है जिसके कारण उनकी हालत दिन-प्रतिदिन बद-से-बदतर होती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि तब भी उपराष्ट्रपति के समर्थन में कट्टरपंथी उर्दू प्रेस मैदान में कूद पड़ा था।

हिंदू युवक की हत्या के मामले में विवादित मौलाना गिरफ्तार

मुंबई उर्दू न्यूज (31 जनवरी) के अनुसार अहमदाबाद में सोशल मीडिया पर पैगम्बर के बारे में कथित विवादित पोस्ट डालने वाले किशन भरवाड की हत्या के मामले में गुजरात एटीएस ने बरेलवी विचारधारा के विवादित मौलाना कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना गनी पर उत्तेजक भाषण देने, नफरत का वातावरण पैदा करने और किशन भरवाड की हत्या के आरोपी बशीर को उकसाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार कमर गनी उस्मानी ने एक कट्टरपंथी संगठन तहरीक फरोग-ए-इस्लाम भी बना रखा है। गत वर्ष त्रिपुरा दंगों में भी दोनों संप्रदायों में नफरत भड़काने के आरोप में इस मौलाना की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। किशन की हत्या 25 जनवरी को हुई थी। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर उसने पैगम्बर और मुसलमानों से संबंधित कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद से वह

कट्टरपंथियों के निशाने पर था। किशन का कत्ल करने वाले आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कमर उस्मानी से उनकी भेंट मुंबई में हुई थी। उस्मानी ने उनसे कहा था कि जो भी व्यक्ति इस्लाम, पैगम्बर और मुसलमानों के खिलाफ बोलता है उसे खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने किशन को मारने की साजिश रची और उसका कत्ल कर दिया।

किशन की हत्या के बाद गुजरात के अनेक नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए, जिसके बाद गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा एटीएस को सौंप दिया। कहा जाता है कि किशन की हत्या मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने गोली मारकर की थी। इस हत्या के बाद गुजरात में तनाव फैल गया था और कई जगह पर उग्र प्रदर्शन हुए थे, जिनमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। इस विवाद में फिल्म स्टार कंगना रनौत भी कूद पड़ी थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि यह हत्या सुनियोजित है और मौलाना कमर गनी उस्मानी के इशारे पर इस साजिश को रचा गया था। कंगना ने यह भी लिखा था कि "मृतक किशन की उम्र 27 वर्ष थी और उसकी एक बेटी भी है। किशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसके बाद उसे माफी मांगने को कहा गया था और उसने माफी भी मांग ली थी। इसके बावजूद उसे दिनदहाड़े कत्ल कर दिया गया। किशन जैसे लोग हमारे देश को अफगानिस्तान बनने से रोक रहे हैं। इसलिए किशन की विधवा को पेंशन देनी चाहिए।"

पुलिस के अनुसार किशन भरवाड ने 6 जनवरी को सोशल मोडिया पर विवादित पोस्ट डाला था। हालांकि इस पर विवाद होने पर उसने वीडियो हटा ली थी और माफी भी मांग ली। 20 जनवरी को शब्बीर अहमदाबाद आकर मौलाना मोहम्मद अयूब जावरवाला से मिला जिसने उसे एक पिस्तौल और पांच गोलियां दी। इसके बाद वह पांच दिनों तक किशन का पता लगाता रहा। 25 जनवरी को दिनदहाड़े उसने किशन की गोली मारकर हत्या कर दी। जब इस निर्मम हत्या के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा तो पुलिस ने इम्तियाज और शब्बीर के साथ जमालपुर से मौलाना अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया। जनाक्रोश को देखते हुए इस घटना की जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने एटीएस को सौंपा। एटीएस ने इस संदर्भ में आठ लोगों को हिरासत में ले लिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 फरवरी) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि राजकोट, वडोदरा, सूरत आदि अनक नगरों में जनप्रदर्शन जारी है और कई नगरों में पूर्ण रूप से हड़ताल है। गुजरात में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लिया हुआ था जिसमें लिखा था, 'किशन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।' समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद गुजरात के अनेक जिलों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने 133 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है जिनमें 64 महिलाएं भी शामिल हैं।

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार पुलिस ने तहरीक फरोग-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ के लिए गुजरात ले जाया गया है। मुस्लिम वकील महमूद पराचा ने कहा कि हम किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन बिना कारण किसी निर्दोष को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। हम इन सारे मामलों की कानूनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद ही अदालती कार्रवाई करेंगे। हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है।

नवभारत टाइम्स (31 जनवरी) के अनुसार किशन भरवाड की हत्या के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवो ने बताया कि हमने किशन भरवाड हत्याकांड को अहमदाबाद अपराध शाखा से गुजरात एटीएस को स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभ में पुलिस ने शब्बीर, इम्तियाज और मौलवी याकूब को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ करने के लिए न्यायालय से नौ दिनों का रिमांड लिया है। अब तक पुलिस इस संदर्भ में आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें राजकोट के दो व्यक्ति भी शामिल हैं। इन्होंने हत्या के लिए मौलवी को पिस्तौल और गोलियां उपलब्ध करवाई थी।

टिप्पणी : तहरीक फरोग-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना कमर गनी उस्मानी शुरू से ही सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में लगा हुआ है। कुछ महीने पूर्व उसने दिल्ली में पत्रकार सम्मेलन को आयोजित करते हुए मुसलमानों को रसूल और इस्लाम के नाम पर भड़काने का प्रयास किया था और यह घोषणा की थो कि कुरान और रसूल का अपमान वह किसो भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और इस संदर्भ में देश भर में मुसलमानों की ओर से जबर्दस्त आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यूट्यूब चैनल 'हिंदुस्तान लाइव' के अनुसार उसने आरोप लगाया था कि हाल ही में देश भर में रसूल और कुरान की तौहीन की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। रसूल और कुरान हमें बेहद अजीज है। इसके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। मौलाना क इस पत्रकार सम्मेलन का मीडिया ने नजरअंदाज किया। इसके बाद मौलाना ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की, जिसकी दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद उसने अपने कुछ साथियों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मौलाना उस्मानी का दावा है कि वह अमेठी की दरगाह हजरत बंदगी मियां का सज्जादानशीन है। मगर आजकल वह दिल्ली में ही रहता है।

त्रिपुरा में हुए दंगों के दौरान यह विवादित मौलाना अपने तीन साथियों के साथ त्रिपुरा पहुंच गया। उसकी गतिविधियों को देखते हुए वहां की पुलिस ने उसे यूएपीए के अतिरिक्त दंगे की साजिश रचने, दो संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने आदि के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। जब जमानत के लिए उसे न्यायालय में पेश किया गया तो न्यायालय ने उसे जमानत देने से इंकार कर

दिया। न्यायालय के इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देते हुए वकील महमूद पराचा ने कहा था कि इस मामले में इन लोगों पर यूएपीए नहीं बनता। उनकी इस दलील को स्वीकार करते हुए मौलाना और उसके तीन सहयोगियों को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था।

दिल्ली के कब्रिस्तानों में दफन के लिए जगह की कमी

दिल्ली में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी के कारण अब राजधानी के मुस्लिम कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने में परेशानी हो रही है।

इंकलाब (13 जनवरी) के अनुसार दिल्ली गेट कब्रिस्तान में शवों को दफन करना बंद कर दिया गया है। इसलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वे कब्रिस्तानों में पक्की कब्रें न बनाएं क्योंकि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो शवों को दफन करने क लिए काई स्थान नहीं बचेगा और दिल्ली वालों को शवों को दफन करने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थान ढूंढना होगा। समाचारपत्र ने दावा किया है कि राजपत्र अधिसूचना 1970 के अनुसार दिल्ली में 448 कब्रिस्तान थे। मगर अब इनमें से सिर्फ 25 कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पर शवों को दफनाया जा रहा है। शेष सभी कब्रिस्तानों का या तो नामोनिशान मिट चुका है या उन पर अवैध कब्जे करके कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं। उदाहरण के रूप में ख्वाजा बाकी बिल्लाह कब्रिस्तान, मेंहदियां कब्रिस्तान और पंचपीर कब्रिस्तान में अब शव दफनाने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। इन कब्रिस्तानों के प्रबंधक शव दफन करने वालों से भारी धनराशि अवैध रूप से वसूल करते हैं। जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है कि कब्रिस्तान के प्रबंधक प्रति कब्र 2000 रुपये से अधिक की धनराशि नहीं वसूल कर सकते। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह भी निर्देश जारी किया है कि किसी भी कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने की अनुमति न दी जाए।

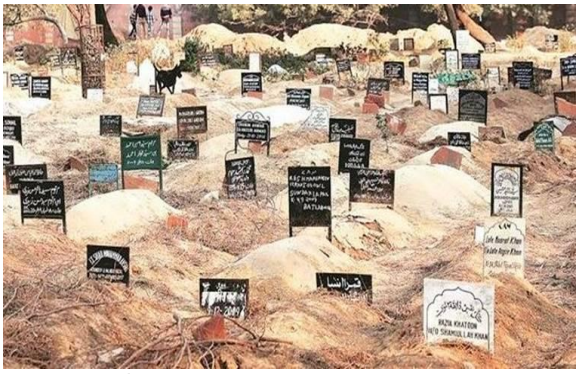

रोजनामा सहारा (16 जनवरी) के अनुसार दिल्ली के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने कहा है कि पक्की कब्रें बनाना इस्लामिक शरा के खिलाफ हैं और यह गुनाह है। इस संदर्भ में दिल्ली के पांच मुफ्तियों ने एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया है और कहा है कि पक्की कब्रें बनाने को रोका जाए। क्योंकि यह इस्लाम के खिलाफ हैं और इससे भविष्य में मुसलमानों के लिए भारी परेशानी होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह निर्देश दिया था कि कोरोना से मरने वालों को सिर्फ मिलेनियम पार्क कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए। इसका विरोध कुछ हिंदू संगठनों ने किया था। जिसके बाद दिल्ली गेट कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वालों के दफन का सिलसिला शुरू किया गया था। मगर क्योंकि अब वहां जगह नहीं है इसलिए मुसलमानों के सामने यह समस्या आ रही है कि कोरोना में मरने वालों को कहां दफनाया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य जमाल अख्तर का कहना है कि वे इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय में जाएंगे।

भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित

इंकलाब (16 जनवरी) के अनुसार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा शासित राज्यों में हैं। यह भी कहा है कि भाजपा मुसलमानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुसलमानों से अपील की है कि वे आने वाले पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा को सफल बनाएं। क्योंकि अन्य दल अभी तक मुस्लिम मतदाताओं में भय का वातावरण बनाकर सत्ता में आने के लिए उनका शोषण करते रहे हैं। मंच ने एक अपीलनामा भी तैयार किया है जिसे मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार और राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने जारी किया है। इसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में अल्पसंख्यक मतदाताओं में बांटा जाएगा। इसमें मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का विवरण पेश किया गया है। मंच ने दावा किया है कि जब से केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है देश में कोइ सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और मुसलमानों के उत्पीड़न की घटनाएं समाप्त हो गई हैं। भाजपा के शासन में देश के मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए वे अपना वोट समझदारी से दें। क्योंकि मामूली सी गलती भी भविष्य में उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

इंकलाब (25 जनवरी) के अनुसार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के दौरे पर है और वह मुस्लिम बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे इन चुनावों में भाजपा के पक्ष में अपना वोट दें। इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शाहिद अख्तर, मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष बिलाल उर रहमान, मंच के सह-संयोजक मोहम्मद मजाहिर खान, हिंदुस्तान फर्स्ट के सदस्य बदरूद्दीन खान आदि शामिल हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का यह प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद पहुंचा और उसने जामिया कासमिया अल जकारिया के मदरसे में मुसलमानों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने विपक्षियों द्वारा इस दुष्प्रचार का खंडन किया कि भाजपा सरकार की कोई भी मंशा किसी भी इस्लामिक मदरसे पर पाबंदी लगाने या उन्हें बंद करने की है। उत्तर प्रदेश सरकार न इस्लामिक मदरसों के आधुनिकीकरण और उनके अध्यापकों के आवास के लिए 2400 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है। भाजपा सरकार का प्रयास है कि देश के अन्य नागरिकों की तरह मुसलमानों का भी विकास हो। उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा देश के विभिन्न भागों में होने वाली धर्म संसदों के बारे में मुसलमानों में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। हालांकि उससे भाजपा या संघ के किसी भी संगठन का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मुसलमानों को इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए।

रोजनामा सहारा (22 जनवरी) के अनुसार इंद्रेश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें नई रोशनी, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, नई मंजिल और हुनर हाट शामिल हैं। गत वर्ष के बजट में मुसलमानों के कल्याण के लिए 4700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकारें खामोशी से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। भाजपा ने देश के अन्य राजनीतिक दलों की तरह मुसलमानों को कभी सिर्फ वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देखा।

दरगाह की पूर्व प्रबंध समिति पर करोड़ों के घोटाले का आरोप

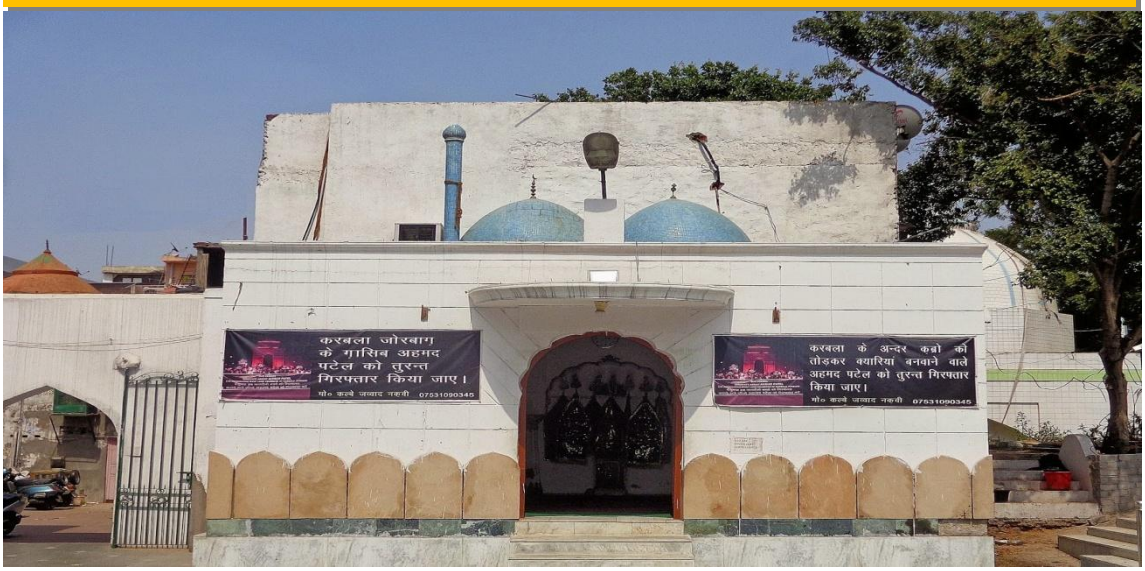

दिल्ली स्थित देश की बेशकीमती शिया दरगाह दरगाह शाह मर्दान की सभी पुरानी प्रबंध समितियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अवैध घोषित करते हुए भंग करने की घोषणा की है और नई प्रबंध समिति का गठन किया है।

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार नई प्रबंध समिति के महामंत्री सरफराज हुसैन ने एक पत्रकार सम्मेलन में पुरानी प्रबंध समिति पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी प्रबंध समितियों के फैसलों की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि एक फर्जी प्रबंध समिति वर्षों से अपनी मनमानी चलाती आ रही थी और उसने इस दरगाह के फंड में जो घोटाला किया है उसका पता लगाकर उसकी एक एक पाई को घोटालेबाजों से वसूल किया जाएगा।

रोजनामा सहारा (30 जनवरी) के अनुसार दरगाह शाह मर्दान की प्रबंध समिति ने वक्फ बोर्ड में 11 लोगों को मनोनीत किया है। यह नई प्रबंध समिति कर्बला और दरगाह से संबंधित सभी वक्फ संपत्तियों के कामकाज को देखेगी। बोर्ड ने यह दावा किया है कि नई प्रबंध समिति का उद्देश्य शिया वक्फ को बेहतर ढंग से चलाना है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नई प्रबंध समिति में सैयद इतजा रजा जैदी को अध्यक्ष, जफरयाब हुसैन को उपाध्यक्ष और सरफराज हुसैन को महामंत्री मनोनीत किया है। नई प्रबंध समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान का धन्यवाद करते हुए यह कहा है कि उनका यह कदम शिया संप्रदाय के हित में है। नई प्रबंध समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।

रोजनामा सहारा (25 जनवरी) के अनुसार यह फैसला वक्फ बोर्ड ने 5 जनवरी 2022 की बैठक में किया था। वक्फ बोर्ड के अनुसार इस दरगाह पर अंजुमन हैदरी के स्वयंभु महासचिव बहादुर अब्बास नकवी और उपाध्यक्ष रईस अब्बास काजमी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और इसके फंड में करोड़ों रुपये के घोटालों की शिकायतें वक्फ बोर्ड के पास प्राप्त हुई थीं। वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने इस वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर रखा था उन्होंने घोटालों की जांच के लिए वक्फ बोर्ड को सहयोग करने से

इंकार कर दिया था। इसलिए वक्फ बोर्ड को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी।

गौरतलब है कि दिल्ली में शिया संप्रदाय से संबंधित विभिन्न वक्फों का प्रबंधन चार शिया संगठन करते हैं, जिनमें एक अंजुमन हैदरो भी है। इन सभी संगठनों के पदाधिकारियों का चुनाव वक्फ बोर्ड की निगरानो और निर्देश में किया जाता है, जिसे बाद में वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होती है। मगर दरगाह शाह मर्दान पर अवैध रूप से काबिज अंजुमन हैदरी ने कभी मंजूरी नहीं ली और उन्होंने खरबों रुपये की इस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।

2019 में अंजुमन हैदरी ने यह दावा किया था कि उसने अपने पदाधिकारियों का चुनाव करवा लिया है और इसमें 20 पदाधिकारियों के निर्विरोध चुने जाने का दावा किया गया था। जबकि असंतुष्ट गुट ने यह आरोप लगाया था कि खरबों रुपये की इस भूमि पर कब्जा करने के लिए यह चुनाव धांधली से करवाया गया है और अंजुमन हैदरी के 700 सदस्यों को इस चुनाव में मतदान करने से रोका गया है। जबकि दूसरी ओर चुनाव समिति के संयोजक मौलाना कल्बे जवाद नकवी के अनुसार नय्यर अली तकवी को अध्यक्ष, बहादुर अब्बास को महामंत्री और शहरयार रिजवी को संयुक्त सचिव चुना गया था। इसके अतिरिक्त कार्यसमिति के 12 सदस्यों के नामों की भी घोषणा की गई थी। इस निर्वाचन को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मान्यता देने से इंकार कर दिया था। उनका कहना था किइस चुनाव पर वक्फ बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण मतदान नहीं हुआ। मगर सीधे ही सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई। अंजुमन हैदरी का दावा था कि वह वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं और उनका अलग ट्रस्ट है। इसलिए उन्हें वक्फ बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है।

टिप्पणी: दरगाह शाह मर्दान देश की सबसे अमीर शिया दरगाह है जो कि नई दिल्ली के सबसे पॉश और महंगे इलाके जोरबाग में स्थित है। इस दरगाह की वक्फ भूमि 165 एकड़ बताई जाती है। इस भूमि के एक एकड़ का बाजार मूल्य इस समय कम-से-कम 100 करोड रुपये है। इसलिए इस भूमि को हड़पने के लिए शिया संप्रदाय के विभिन्न गुट दशकों से संघर्ष करते आ रहे हैं। दिल्ली की पुरानी बस्ती अलीगंज में दरगाह शाह मर्दान का निर्माण 15वीं शताब्दी में एक शिया आसिफ शाह ने करवाया था। इस दरगाह में हजरत अली का एक पदचिन्ह रखा हुआ है। इस दरगाह का इस्तेमाल कर्बला के तौर पर भी ताजियों को दफनाने के लिए होता आ रहा है।

बताया जाता है कि इस दरगाह का पुराना नाम कदम शरीफ था और उसके नाम 165 एकड़ वक्फ भूमि थी। देश के विभाजन के बाद पुनर्वास मंत्रालय ने इस दरगाह की अधिकांश भूमि का अधिग्रहण करके वहां पर शरणार्थियों के लिए अलीगंज नामक एक कॉलोनी बसाई थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1719 में तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की एक पत्नी कुदिशिया बेगम ने इस दरगाह में बंगला तर्ज के कई भवनों का निर्माण करवाया था। इस दरगाह में एक भवन में बीबी की चक्की भी रखी हुई है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा बेगम इसका इस्तेमाल किया करती थी। कहा जाता है कि कभी इस दरगाह की भूमि सफदरजंग मकबरे तक फैली हुई थी। जब 1911 में अंग्रेजां ने नई दिल्ली का निर्माण किया था तो भी इस दरगाह की काफी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मगर मूल दरगाह और 40 एकड़ भूमि को छोड़ दिया गया था। इस क्षेत्र में क्योंकि दिल्ली की सबसे महंगी कॉलोनियों का निर्माण हो चुका है इसलिए इस दरगाह की भूमि बेशकीमती है। यही कारण है कि इसके कब्जे को लेकर शियाओं के विभिन्न गुटों में संघर्ष होता आ रहा है।

विश्व

रूसी हमले की आशंका से यूक्रेन में तनाव

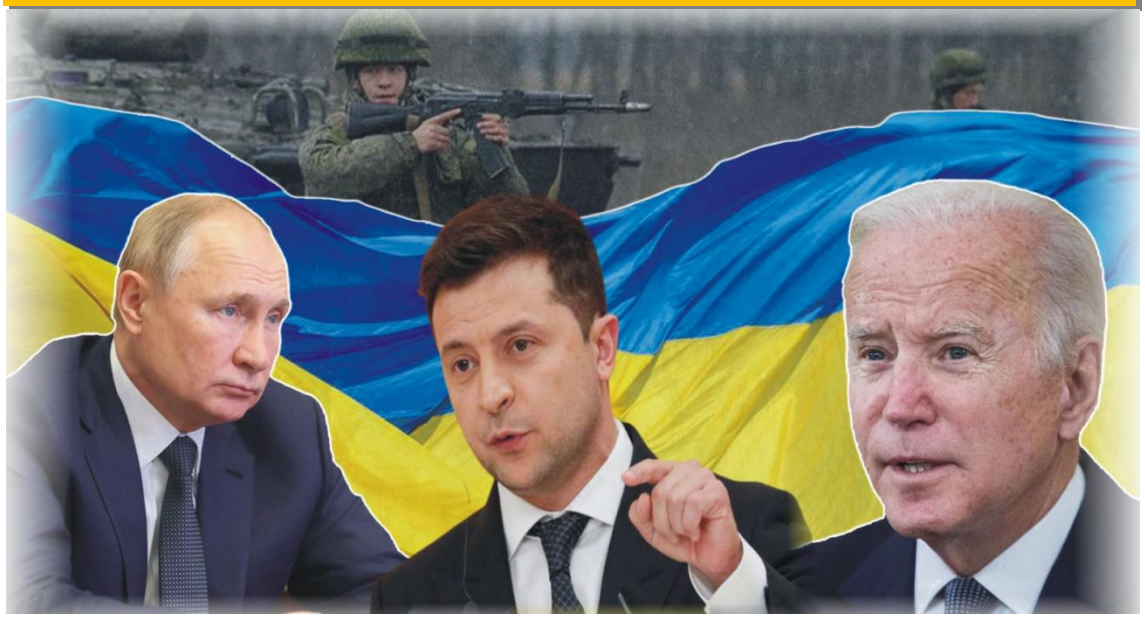

यूक्रेन व रूस की सीमा पर स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। इस पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद का विशेष अधिवेशन बुलाने की घोषणा की है ताकि तीसरे विश्व युद्ध को शुरू होने से रोका जा सके।

रोजनामा सहारा (30 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रन पर हमला करने वाला है इसलिए उसने अपने दूतावास के सभी कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। ऐसी ही घोषणा ब्रिटेन ने भी की है।

रोजनामा सहारा (29 जनवरी) के अनुसार रूस टैंकों, तोपों और अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश एक लाख सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है। लेकिन रूस का दावा है कि वह हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगले महीने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा यूक्रेन के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद की है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मास्को युद्ध नहीं चाहता मगर वह अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने हितों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार अगर रूस यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी होगी। आमतौर पर रूस और यूक्रेन की सीमा पर 35 हजार रूसी सैनिक तैनात रहते हैं। मगर अब उनकी संख्या बढ़ाकर एक लाख 60 हजार तक कर दी गई है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन को रूस में पुनः मिलाए जाने के 15000 समर्थक भी यूक्रेन के विभिन्न भागों में सक्रिय हैं।

रोजनामा सहारा (30 जनवरी) ने इस विवाद के संबंध में अनेक लेख प्रकाशित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 1991 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन में शामिल था। मगर इसके बाद यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हो गया था और

उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। रूस इन दिनों पुनः ताकतवर हो गया है और वह यह नहीं चाहता कि अमेरिका उसकी सीमाओं पर अपना कोई अड्डा बनाए। 2014 के पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था मगर अब उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब रूस यूक्रेन पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहा है जो कि अमेरिका और उसके नाटो संधि के सहयोगियों को किसी भो कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। यूरोपीय देशों को इस बात का भय है कि अगर यूक्रेन विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। रूस का यह प्रयास है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो संधि से अलग रखा जाए। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यह रूस के लिए बेहद खतरनाक होगा। यूक्रन के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के एक बड़े भाग की सीमा रूस के साथ मिलती है। रूस का यह प्रयास है कि यूक्रेन में उसकी समर्थक सरकार सत्ता में हो। 2010 में हुए चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए थे जो कि रूस समर्थक माने जाते थे। उन्हांने यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने की संधि को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ वहां पर जनाक्रोश भड़क उठा और उन्हें 2014 में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। यूक्रेन को अपने प्रभाव में रखने के लिए रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जर्मनी आर फ्रांस ने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया मगर वे विफल रहे।

इत्तेमाद (21 जनवरी) ने अपने संपादकीय में यह चेतावनी दी है कि यूक्रेन विवाद से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जेनेवा में अमेरिका और रूस के बीच जो वार्ता हुई थी वह विफल हुई है। वहां पर स्थिति विस्फोटक है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी यह चाहते हैं कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर जो एक लाख सैनिक इकट्ठे कर रखे हैं उन्हें वहां से हटाया जाए।

दूसरी ओर रूस इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप की ओर हर कीमत पर रोका जाए। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिद्द पर अड़े हुए हैं। स्थिति के विस्फोटक होने का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर कभी भी जंग छिड़ सकती है। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों ने अपने दूतावासों के कर्मचारियों को यूक्रेन से वापस बुला लिया है। अभी तक यूक्रेन विधिवत रूप से नाटो संधि में शामिल नहीं हुआ है। रूस पश्चिमी देशों से इस बात का आश्वासन चाहता है कि व भविष्य में कभी भी यूक्रेन को नाटो संधि में शामिल नहीं करेंगे। जबकि इस तरह का कोई आश्वासन देने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी तैयार नहीं हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए हैं। जबकि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को कई तरह के मिसाइल उपलब्ध कराए हैं। मगर जर्मनी ने यूक्रेन को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने से इंकार कर दिया है।

पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद

रोजनामा सहारा (28 जनवरी) के अनुसार बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हमला करके दस पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। समाचारपत्र 'डॉन' के अनुसार सेना की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आतंकवादियों ने 25-26 जनवरी की रात को दक्षिणी बलूचिस्तान में एक सैनिक चौकी पर हमला किया और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाकर दस पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। जबकि सेना ने इस क्षेत्र में ली गई सघन तलाशी के बाद तीन कथित आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित बलूची क्षेत्र में लंबे समय से बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी के जिहादी सक्रिय हैं जो कि पाकिस्तान के शोषण से बलूचियों को मुक्ति दिलाकर आजाद बलूचिस्तान की स्थापना करने के लिए संघर्षशील हैं। सेना ने घोषणा की है कि पाकिस्तान की एकता और सार्वभौमिकता को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा और हर कीमत पर विद्रोहियों को कुचल दिया जाएगा।

इंकलाब (16 जनवरी) के अनुसार लाहौर में हुए एक धमाके में अलेक लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह धमाका लाहौर के सबसे बड़े बाजार अनारकली में हुआ। लाहौर पुलिस के प्रवक्ता राना आरिफ ने इस धमाके में विदेशियों द्वारा संचालित आतंकवादियों का हाथ बताया है और कहा है कि ये बम एक मोटर साइकिल में लगाया गया था, जिसमें रिमोर्ट कंट्रोल से विस्फोट किया गया। इस धमाके में दो फुट गहरा गडढ़ा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बज़दार ने इस धमाके के पीछे विदेशी एजेंटों का हाथ बताया है और कहा है कि इस धमाके के दोषियों का पता लगाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुस्लिम लीग (नवाज) की उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि जबसे इमरान खान सत्ता में आए हैं आतंकवाद की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है।

रोजनामा सहारा (22 जनवरी) के अनुसार अनारकली बाजार में हुए धमाके के बारे में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो से तीन संदिग्ध व्यक्तियों की निशानदेही की है और दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। इस धमाके में पांच मोटरसाइकिल तबाह हुए हैं। यह धमाका एक स्टेशनरी की दुकान के समीप हुआ है।

तालिबान द्वारा प्रेस कांफ्रेंस के आयोजन पर प्रतिबंध

सियासत (28 जनवरी) के अनुसार तालिबान ने काबुल में किसी भी प्रेस कांफ्रेंस के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेंटर की ओर से 26 जनवरी को एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करन की घोषणा की गई थी, जिसमें विदेशी मीडिया के 11 प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। मगर तालिबान ने इस पत्रकार सम्मेलन को रद्द करवा दिया और कहा है कि जब तक सरकार अनुमति नहीं देती किसी भी तरह की प्रेस कांफ्रेंस का अफगानिस्तान में आयोजन नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन के प्रमुख अली असगर अकबरजादा ने आरोप लगाया है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद मीडिया की अधिकांश गतिविधियां ठप हैं और 90 प्रतिशत मीडियाकर्मी रोजगार से हाथ धो चुके हैं।

रोजनामा सहारा (1 फरवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पूर्व सरकार से संबंधित 100 से अधिक कर्मचारियों को गोली से उड़ा दिया गया है। तालिबान का गुप्तचर विभाग चुन-चुनकर अमेरिका से संबंधित सहयोगियों को तलाश कर रहा है ताकि उनका सफाया किया जा सके। इसके अतिरिक्त पुरानी सरकार के सुरक्षा सैनिकों से संबंधित कम-से-कम सौ लोगों को तालिबान ने सार्वजनिक रूप से गोली से उड़ाया है।

हमारा समाज (18 जनवरी) के अनुसार तालिबान ने घोषणा की है कि मार्च महीने के बाद पूरे देश में सभी छात्राओं के स्कूल खोल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आए हैं उन्होंने छात्राओं और महिलाओं के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। दा दशक पूर्व भी जब तालिबान सत्ता में आए थे तो उन्होंने महिलाओं के

पढ़ने, नौकरी करने और घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह निर्देश दिया था कि वे कड़े पर्दे का पालन करें। हाल ही में पर्दा का पालन न करने वाली कई दर्जन महिलाओं को तालिबान ने सार्वजनिक रूप से गोली से उड़ा दिया था। मगर अब विश्व संगठनों के दबाव के कारण तालिबान को लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर विचार करना पड़ रहा है। तालिबान के उपसूचना मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर सह-शिक्षा को लागू नहीं करेंगे। क्योंकि यह इस्लाम और शरा के खिलाफ है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूल होने चाहिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अफगानिस्तान क 34 सूबों में से किसी भी सूबे में अभी तक छात्राओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी गइ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के विभिन्न संगठनों से अपील की है कि वे 30 लाख अफगानों को भूखमरी और सर्दी से होने वाली मौतों को बचाने के लिए पांच अरब डॉलर की सहायता मानवीय आधार पर उपलब्ध करवाएं।

सियासत (20 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने विश्व भर के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता दें क्योंकि इसके बाद ही हम विकास कर सकते हैं। गौरतलब है कि अभी तक किसी भी पश्चिमी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी ह।

फिलीपींस भारत से मिसाइल प्रणाली खरीदेगा

इंकलाब (17 जनवरी) के अनुसार फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने का निर्णय किया है, जिसकी लागत 375 मिलियन डॉलर होगी। फिलीपींस सरकार का दावा है कि इससे उसकी नौसेना की रक्षा और मारक शक्ति में भारी वृद्धि होगी। इस संबंध में दोनों देशों के बीच विधिवत समझौता हो चुका है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत में बने हुए मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस तटीय क्षेत्रों में लगाएगा ताकि उनके द्वारा शत्रुओं क जलयानों को समुद्र में ही निशाना बनाया जा सके। फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए गत पांच वर्षों से भारत से वार्ता हो रही थी मगर कोरोना की महामारी के कारण इस सौदे में देरी हुई है। भारत में बनाए गए मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस के 200 मील तटीय क्षेत्र में लगाया जाएगा। फिलीपींस ने अपनी

सेना को सुदृढ़ और सशक्त बनाने और उसकी मारक क्षमता में वृद्धि करने की जो पंचवर्षीय योजना बनाई है यह उसी का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि इस समय फिलीपींस की जलसेना के पास जो सैनिक अस्त्र-शस्त्र हैं वे बहुत पुराने हैं। इससे पूर्व फिलीपींस ने इजरायल से भी काफी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र खरीदे थे, जिन्हें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

सिंगापुर में पैगम्बर के विवादित कार्टून पर प्रतिबंध

इंकलाब (15 जनवरी) के अनुसार सिंगापुर सरकार ने एक पुस्तक के प्रकाशन और उसके वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि उसमें पैगम्बर इस्लाम से संबंधित कुछ विवादित और अपमानजनक कार्टून शामिल हैं। मुस्लिम मामलों के मंत्री मासागोस जुल्किफ्ली ने कहा कि इस पुस्तक का नाम 'रेड लाइंस : पॉलिटिकल कार्टूनस् एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट सेंसरशिप' है। प्रकाशकों का यह दावा है कि यह पुस्तक इस्लाम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रकाशित की गई है और उनका यह भी कहना है कि इसका लक्ष्य किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। मगर सिंगापुर की सरकार यह महसूस करती है कि पैगम्बर इस्लाम से संबंधित कोई भी विवादित मामला मुसलमानों के लिए बेहद संवेदनशील है। अगर इस पुस्तक के सिंगापुर में प्रवेश और वितरण की अनुमति दी गई तो उससे दंगे भड़क सकते हैं। इसलिए सरकार ने इस पुस्तक को देश में लाने और उसका वितरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पश्चिम एशिया

संयुक्त अरब अमीरात पर हूती विद्रोहियों का हमला

इंकलाब (1 फरवरी) के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों ने उस होटल को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसमें इजरायली राष्ट्रपति को ठहराया गया था। मगर संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा तंत्र ने इस हमले को विफल बना दिया और किसी प्रकार का जान व माल का नुकसान नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार हूतियों द्वारा दागे गए मिसाइल को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हो हवा में तबाह कर दिया गया और इस मिसाइल का मलबा आबादी से दूर जा गिरा।

गौरतलब है कि इजरायल और संयुक्त अरब अमोरात के बीच बढ़ते हुए रिश्तों से नाराज ईरान समर्थक हूती विद्रोही गत दो सप्ताह से संयुक्त अरब अमोरात को अपना निशाना बना रहे हैं। यह तीसरा बड़ा हमला था। इससे पूर्व दो हमले किए जा चुके हैं। यह हमला ऐसे अवसर पर किया गया जब एक दिन पूर्व ही इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग संयुक्त अरब अमोरात के सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले वे पहले इजरायली राष्ट्रपति हैं मगर इस हमले के बावजूद इजरायली राष्ट्रपति के कार्यालय ने यह घोषणा की है कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना दौरा जारी रखेंगे।

गौरतलब है कि ईरान समर्थक हूती विद्रोही यमन में उनके खिलाफ सऊदी अरब द्वारा किए गए हमलों के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात को अपना निशाना बना रहे हैं। जनवरी के प्रारंभ में हूतियों ने संयुक्त अरब अमीरात के जहाज पर कब्जा कर लिया था। हूतियों का यह दावा था कि सऊदी अरब इस जलयान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई कर रहा है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने इस बयान का खंडन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हूतियों से अपील की थी कि वे जहाज वापस लौटा दें। मगर उन्होंने इसे मानने से इंकार कर दिया। हूतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने घोषणा

की है कि सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में विदेशी कंपनियों और नागरिकों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हम इन हमलों में और तेजी लाएंगे और विभिन्न स्थानों को अपना निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने भी अबू धाबी पर मिसाइल हमलों की निंदा की है और कहा है कि सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को अमेरिका सहायता देना जारी रखेगा। हम संयुक्त अरब अमीरात को अपनी सहायता जारी रखेंगे और उसे किसी भी हमले से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों का विमान संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सभी फ्लाइट जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात यमन में हूती विद्रोहयों के खिलाफ लड़ने वाले सऊदी गठबंधन का हिस्सा है। हाल के सप्ताहों में हूतियां ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पर मिसाइल से कई हमले किए हैं। इजरायल के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि हम सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के साथ संबंधों को सुधारने का जो सिलसिला चलाए हुए हैं उसे जारी रखेंगे और हतियों के हमलों का मुकाबला करने और उन्हें कुचलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को हर तरह का सहयोग देंगे।

इंकलाब (18 जनवरी) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहयों ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में विभिन्न ठिकानों पर हमले किए, जिससे दो स्थानों पर आग लग गई। पुलिस के अनुसार दो धमाकों में दो भारतीय और एक पाकिस्तानी मारा गया जबकि छह लोग घायल हुए। हूती प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अंदर फौजी ऑपरेशन किया है। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात सऊदी गठबंधन में शामिल था मगर 2019 में उसने यमन में अपने सैनिकों की संख्या बहुत कम

कर दी थी। मगर संयुक्त अरब अमीरात की ओर से यमन की सरकारी सेना को निरंतर अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए जा रहे हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने 2014 में यमन की राजधानी साना को अपने कब्जे में लकर वहां की सरकार को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। तब से वहां पर युद्ध जारी है। यमन में हो रहे युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग भुखमरी का शिकार हुए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की है कि अमेरिका हूती विद्रोहियों को पुनः आतंकवाद की सूची में डालने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका की इस घोषणा का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह घोषणा की है कि अमेरिका हूतियों के उन्मूलन के लिए सभी कदम उठाएगा। अमेरिका ने हूतियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की वायु सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वहां के अधिकारियों से उच्च स्तर पर बातचीत की है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित 23 जनवरी के समाचार में अमेरिकी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान को आश्वासन दिया है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के अपने वायदे पर दृढ़ है और इस संबंध में सभी संभव कदम

उठाए जाएंगे। सऊदी अरब गठबंधन ने यमन में हूतियों के खिलाफ हमलों में वृद्धि करने की भी घोषणा की है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि हूतियों के अनेक सैनिक शिविरों और अस्त्र-शस्त्रों के भंडारों को निशाना बनाया गया है।

इत्तेमाद (22 जनवरी) के अनुसार यमन की रेड क्रिसेंट सोसायटी ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब की बमबारी से उत्तरी यमन में एक जेल पर हुए हमले में 100 से अधिक कैदी मारे गए हैं। यह हमला जुमा की रात किया गया था। इसके बाद हुदैदाह की बंदरगाह पर भी हमला किया गया, जिसके कारण पूरे यमन में इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। सूचनाओं के अनुसार सऊदी अरब ने यमन में अनेक क्षेत्रों पर भारी बमबारी की है, जिसमें कम-से-कम 200 लोगों के मारे जाने की संभावना है।

हमारा समाज (17 जनवरी) के अनुसार जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान अल-सफादी ने अमेरिका का दौरा किया है और उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि वह अरब के मामलों में हस्तक्षेप करने से बाज आए। वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे।

अवधनामा ने 23 जनवरी के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यमन के हूतियों ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वे मासूम नागरिकों पर हमलों का सिलसिला फौरन बंद करे। वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 जनवरी) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने घोषणा की है कि उनका देश ईरान के साथ निरंतर युद्ध की स्थिति में है। हम ईरान को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने हूतियों पर हमला करने का सिलसिला तेज कर दिया है। ईरान का नामोनिशान मिटाने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे।

सियासत (22 जनवरी) के अनुसार यमन में जब सऊदी अरब समर्थक मंसूर हादी की सरकार को ईरान समर्थक हूतियों के हमलों के कारण साना से भागना पड़ा और उसके बाद वहां पर जो युद्ध शुरू हुआ वह गत सात वर्षों से जारी है। मंसूर हादी और उनका मंत्रिमंडल सऊदी अरब में शरण लेकर वहां से निर्वासित सरकार चला रहे हैं। हाल ही में इस युद्ध में जो तेजी आई है उससे अरब जगत में व्यापक रूप से युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। भारत ने अबू धाबी में हूतियों द्वारा हमले की निंदा की है। अभी तक भारत इस विवाद से अपनी दूरी बनाए हुए था। क्योंकि भारत के सऊदी अरब और ईरान दोनों से दोस्ताना संबंध थे। मगर अब हालात बदले हैं और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अबू धाबी पर हुए हमले की निंदा की है।

सऊदी अरब और इंडोनेशिया से राजनयिक संबंध बनाएगा इजरायल

सियासत (27 जनवरी) के अनुसार इजरायल के विदेश मंत्री यैर लापिड ने कहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल के चार मुस्लिम देशों के साथ जो शांति समझौते हुए थे उसके आधार पर हम सऊदी अरब और इंडोनेशिया से राजनयिक संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं। मगर इन दोनों देशों से किसी भी तरह का समझौता करने में कुछ समय लगेगा। इस्लाम के पवित्र स्थान सऊदी अरब और दुनिया में मुस्लिम जनसंख्या के सबसे बड़े देश इंडोनेशिया दोनों 1967 के युद्ध में इजरायल द्वारा कब्जे किए गए क्षेत्रों में अभी तक फिलिस्तीनियों की आजाद सरकार की स्थापना के इच्छुक थे। इसके बाद ही वे इजरायल के साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित करना चाहते थे।

मगर इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ अमेरिका के सहयोग से जो समझौते किए हैं, वह अब अन्य मुस्लिम देशों तक भी बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि कई छोटे मुस्लिम देश इजरायल के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं।

इत्तेमाद (28 जनवरी) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इजरायल के राष्ट्रपति ने तुर्की का सरकारी दौरा करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत होगी। तुर्की इजरायल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने

के लिए तैयार है। तुर्की पहला मुस्लिम देश था, जिसने मार्च 1949 में इजरायल को मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में अनेक बार उतार चढ़ाव आया।

सऊदी अरब में महलों को होटलों में बदलने की योजना

रोजनामा सहारा (23 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब ने अपने आर्थिक विकास को नया आयाम देने का फैसला किया है। वह अब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल की बिक्री तक सीमित नहीं रखना चाहता। इसलिए सऊदी सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह अपने कई शाही महलों को लग्जरी होटल में बदलेगा। यह फैसला पब्लिक इंवेस्टमेंट फंड ने किया है। इसका उद्देश्य देश में होटल व्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देना है। फिलहाल इस योजना के तहत जद्दा के अल हमरा महल और राजधानी रियाद के तुवैक पैलेस और द रेड पैलेस नामक महलों को शानदार होटलों में बदला जा रहा है। इन महलों में 500 से अधिक कमरों की व्यवस्था है।

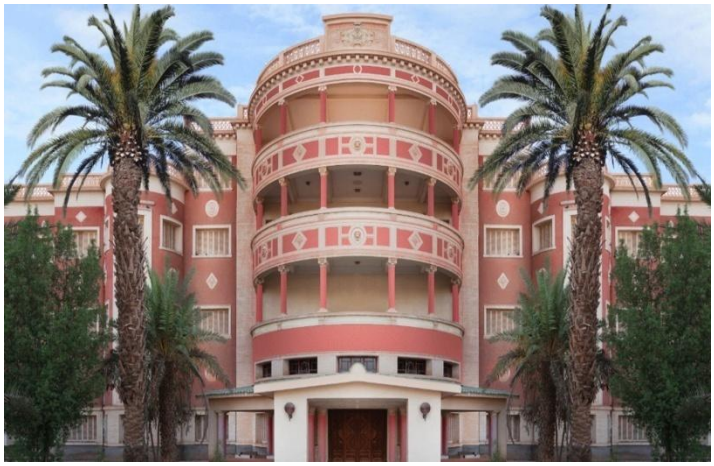

सऊदी सरकार को यह आशा है कि विदेशी पर्यटकों के आने से उसकी अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा और वह केवल तेल के निर्यात पर ही निर्भर नहीं रहेगी। पर्यटन के विकास से उसकी राष्ट्रीय आय में दस प्रतिशत की वृद्धि होगी। सऊदी अरब के शाह सलमान आर उनके 36 वर्षीय बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की कट्टरपंथी छवि को बदलने का फैसला किया है। यही कारण है कि सऊदी अरब में पहली बार 48 सिनेमाघर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कई हेल्थ रिसॉर्ट और लग्जरी रेस्टोरेंट भी खोले गए हैं। पर्यटन को विकसित करने के लिए सऊदी सरकार ने 480 बिलियन डॉलर खर्च करने का फैसला किया है।

सूडान में जनरल बुरहान का नया मंत्रिमंडल

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जनवरी) के अनुसार सूडान की स्वशासी परिषद के प्रमुख अब्दुल फतह अल-बुरहान ने अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा की है जिसमें 15 मंत्रियों को स्थान मिला है। अमेरिका ने गत दिनों यह घोषणा की थी कि अगर सूडान में असैनिक सरकार बहाल नहीं की जाती और वहां पर शांति स्थापित नहीं होती तो वह सूडान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं देगा। मगर इसके बावजूद सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है।

इंकलाब (22 जनवरी) के अनुसार अब तक सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम-से-कम 80 लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारी यह मांग कर रहे हैं कि सूडान का शासन स्थाई रूप से नागरिकों को सौंपा जाए।

इत्तेमाद (16 जनवरी) के अनुसार सूडान में उमर अल- बशीर की 30 वर्षीय सरकार का तख्ता 2019 में पलट दिया गया था और एक स्वशासी परिषद स्थापित की गई थी, जिसमें फौज और जनता के प्रतिनिधि शामिल थे। मगर पिछले वर्ष सेना ने अब्दुल्ला हमदोक को सत्ता से हटाकर शासन पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर महीने से लेकर अब तक जनता सैनिक शासन के खिलाफ देशभर में उग्र प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को सूडानी प्रोफेशनल एसोसिएशन, रेजिस्टंस कमेटी, फोर्सेस फॉर डिक्लेयरेशन ऑफ फ्रीडम एंड चेंज का समर्थन प्राप्त है। इन संगठनों और फौज के बीच हुए समझौते के अनुसार जुलाई 2023 में देश में आम चुनाव करवाकर इन चुनावों में सत्तारूढ़ होने वाली पार्टी को सत्ता सौंपने की व्यवस्था की गई थी। मगर इस समझौते का उल्लंघन करके अक्टूबर 2021 में असैनिक सरकार को बर्खास्त करके सेना ने अपने हाथ में ले ली। सेना के जनरल बुरहान ने यह घोषणा की कि जुलाई 2023 के चुनाव तक सेना सत्तारूढ़ रहेगी और इसके बाद देश में आम चुनाव करवाए जाएंगे। उनमें जो राजनीतिक पार्टी विजयी होगी उसे सत्ता सौंप दी जाएगी।

जनरल बुरहान की इस घोषणा को विश्व के लगभग सभी देशों ने ठुकरा दिया और उन पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि

वे सत्ता को तुरंत असैनिक नेताओं को सौंपें। अमेरिका ने उन पर दबाव डालने के लिए ऐलान किया कि वह तब तक सूडान को 700 करोड़ डॉलर की सहायता नहीं देगा जब तक कि सत्ता पुनः असैनिक सरकार को नहीं सौंपी जाती। लोकतांत्रिक संगठनों की मांग है कि सेना तुरंत सत्ता किसी असैनिक सरकार को सौंपे। जबकि जनरल बुरहान का कहना है कि वे 2023 में चुनाव में निर्वाचित होने वाली पार्टी को ही सत्ता सौपेंगे। तब तक वे सत्ता अपने हाथ में रखेंगे। उनकी जिद्द के कारण सूडान आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है।

ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में पांच इजरायली गिरफ्तार

इंकलाब (16 जनवरी) के अनुसार इजरायल के गुप्तचर विभाग ने ईरान के लिए जासूसी करने वाले एक नेटवर्क को तोड़ने का दावा किया है। आरोप है कि ये इजरायली ईरान को उसक सैनिक ठिकानों की तस्वीरें और अन्य सैनिक उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराया करते थे। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार ये जासूसी नेटवर्क चार महिलाओं और एक पुरुष का था। इनका संबंध ईरान से आए यहूदी परिवारों या उनकी संतानों से है। इन पांचों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि ये आरापी इजरायल की सैनिक तैयारियों के संबंध में ईरान को सूचना दिया करते थे। इजरायल के प्रधानमंत्री ने इस जासूसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए इजरायल के आंतरिक जासूसी संगठन की प्रशंसा की है और कहा है कि ईरानी संगठन पासदारान-ए-इंकलाब निरंतर इजरायल की सरकार में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। इजरायल ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे के खिलाफ धमकियां देने का सिलसिला जारी है।

गौरतलब है कि गत वर्ष ईरान ने यह घोषणा की थी कि उसके परमाणु विकास कार्यक्रम में पलीता लगाने के लिए इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद ने उसके कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवाई थी। इनमें ईरान की परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम का प्रमुख भी शामिल था।

हिंदुस्तानी दवाखाना का नाम बदलने पर विवाद

रोजनामा सहारा (30 जनवरी) के अनुसार दिल्ली के कुछ समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि दिल्ली सरकार ने बल्लोमारान स्थित हिंदुस्तानी दवाखाना का नाम बदलकर आम आदमी पॉलीक्लिनिक रख दिया है। इस पर मुस्लिम क्षेत्रों में भारी विवाद पैदा हो गया था। क्योंकि हिंदुस्तानी दवाखाने की स्थापना कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने की थी आर उसे दिल्ली की विरासत का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। जब इस विवाद ने तूल पकड़ा तो दिल्ली के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री इमरान हुसैन को इस बात की सफाई दनी पड़ी कि दिल्ली सरकार ने हिंदुस्तानी दवाखाने के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया बल्कि 1900 में स्थापित हिंदुस्तानी दवाखाना की हेरिटेज बिल्डिंग में दिल्ली सरकार सुधार कर रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को भी इस बात की सफाई देनी पड़ी। दरअसल यह विवाद बल्लीमारान के भूतपूर्व विधायक हारून युसूफ ने उठाया था और उन्होंने यह दावा किया था कि दिल्ली सरकार ने हिंदुस्तानी दवाखाना का नाम बदलकर आम आदमी पॉलीक्लिनिक रख दिया है।

दारूल उलूम देवबंद का विवादित फतवा

इंकलाब (18 जनवरी) के अनुसार सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन दारूल उलूम देवबंद द्वारा जारी किए गए कुछ फतवों को सरकार ने देश के कानून के खिलाफ बताया है और इस संदर्भ में दारूल उलूम देवबंद को एक नोटिस भी जारी किया है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में किसी व्यक्ति ने यह शिकायत की है कि दारूल उलूम देवबंद ने हाल ही में एक फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चा गोद लेना गैरकानूनी

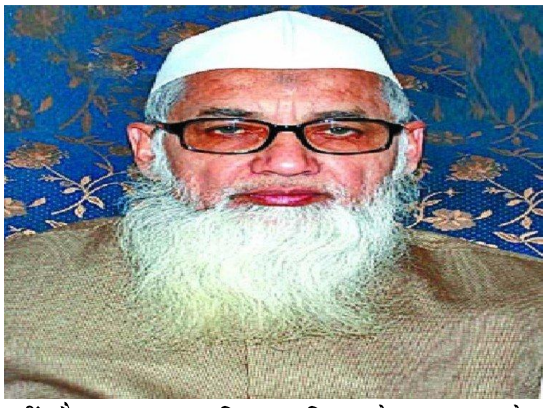

नहीं है। मगर इस्लामिक शरिया के अनुसार गोद लिए बच्चे को विरासत में हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती। कमीशन ने इस शिकायत का नोटिस लिया है और कहा है कि दारूल उलूम देवबंद की ओर से हाल ही में स्कूलों के पाठ्यक्रम, कॉलेजों के यूनिफॉर्म, गैरइस्लामिक माहौल में बच्चों की शिक्षा और सह-शिक्षा के संबंध में अनेक ऐसे फतवे जारी किए गए हैं जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ है। कमीशन ने सहारनपुर के जिलाधिकारी को इस संदर्भ में नोटिस भेजकर जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी यह निर्देश दिया है कि जब तक दारूल उलूम देवबंद इन फतवों को अपनी वेबसाइट से नहीं हटाती तब तक उसे ब्लॉक कर दिया जाए।

समाचारपत्रों में इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधक मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि अभी तक उन्हें आयोग या जिला प्रशासन को ओर से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वे इस समाचार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नोटिस मिलने के बाद इस संदर्भ में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और पर्सनल लॉ का पालन करने की पूरी छूट है। इसलिए उन्होंने जो फतवे जारी किए हैं वे इस्लामिक शरीयत के अनुरूप हैं। इसलिए किसी भी संगठन को हमारी पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

शरई अदालत का उद्घाटन

हमारा समाज (18 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से नवी मुंबई में शरई अदालत स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन दारूल उलूम नदवा के प्राध्यापक मौलाना अतीक अहमद कासमी ने किया। इस शरई अदालत का प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद फैयाज आलम कासमी को नियुक्त किया गया है जो कि मुसलमानों के विभिन्न विवादों का निर्णय शरा और सुन्नत के अनुसार करेंगे। मौलाना कासमी ने मुसलमानों से अपील की कि वे अपने विवादों को अदालत में ले जाने की बजाय शरई अदालतों में ले जाएं। क्योंकि इस समय सरकारी अदालतों में तीन करोड से अधिक विवाद लंबित पड़े हुए हैं।

मुनव्वर राना हैं परेशान

सालार (30 जनवरी) के अनुसार विवादित उर्दू शायर मुनव्वर राना एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर योगी पुनः सत्ता में आ गए तो वे जीवित नहीं बचेंगे। मरना तो वैसे भी है लेकिन बेमौत मैं मरना नहीं चाहता। इसलिए अगर योगी सत्ता में आ गए तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी अन्य राज्य में बारिया-बिस्तर बांधकर चला जाउंगा। गौरतलब है कि मुनव्वर राणा ने अवार्ड वापस

करके सनसनी फैला दी थी। इसके बाद उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। इस पर उनके खिलाफ न्यायालय में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था।

गैरमुसलमानों में इस्लाम का प्रचार

हमारा समाज (19 जनवरी) के अनुसार विख्यात मुस्लिम विचारक एवं दारूल उलूम नदवा के प्रमुख सैयद राबे हसनी नदवी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे गैर मुस्लिम समाज के साथ गहरा संपर्क स्थापित करें ताकि उनमें इस्लाम और पैगम्बर के बारे में जो गलतफहमियां फैलाई गई हैं उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वे ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को इस्लाम में लाएं। यदि कोई मुसलमान यह प्रयास नहीं करता तो कयामत के वक्त उसे अल्लाह को जवाब देना होगा।

नेपाल की राष्ट्रीय सभा में मुस्लिम सदस्य मनोनीत

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार नेपाल के इतिहास में पहली बार एक मुसलमान को राष्ट्रीय सभा के लिए मनोनीत किया गया है। मुफ्ती मोहम्मद खालिद सिद्दीकी जनता समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे। उन्होंने मार्क्सवादी पार्टी के उम्मीदवार उस्मान अंसारी को चुनाव में हराया है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वृद्ध व्यक्ति से मांगी माफी

रोजनामा सहारा (31 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने एक 82 वर्षीय बुजुर्ग आयकरदाता से वसूल की गई टैक्स की धनराशि 15 महीने बाद वापस लौटाए जाने के लिए माफी मांगी है। समाचारपत्र 'डॉन' के अनुसार अल्वी ने कहा है कि इस लालफीताशाही पर आपका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए और इस मामले के दोषी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार मोहम्मद खान नामक एक व्यक्ति ने 19 अक्टूबर 2020 को टैक्स के रिफंड के लिए याचिका दायर की थी। जब उसकी याचिका पर 15 महीने तक कोई कार्रवाई

नहीं हुई तो उसने इस लालफीताशाही की ओर पाकिस्तानी राष्ट्रपति का ध्यान दिलाया था। राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद आयकर विभाग ने उन्हें काटे गए टैक्स की वापसी की है। इस घटना पर राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से खेद प्रकट किया है और मोहम्मद खान को पत्र भेजकर उनसे क्षमा मांगी है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

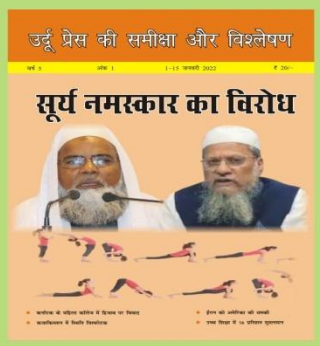

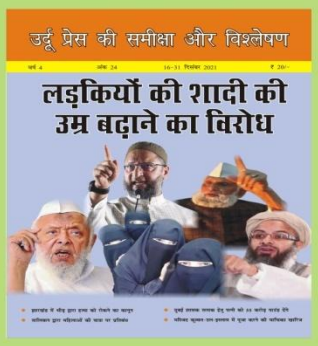

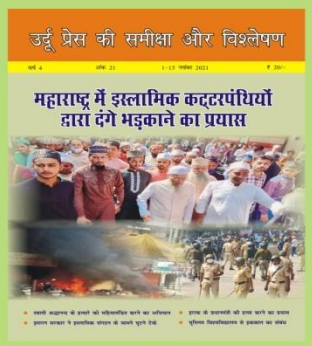

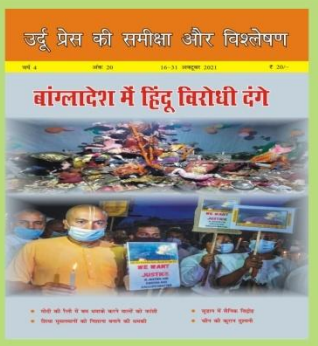

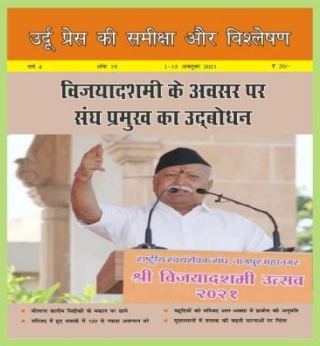

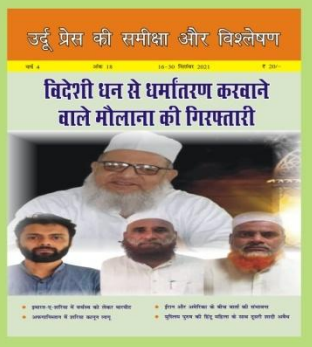

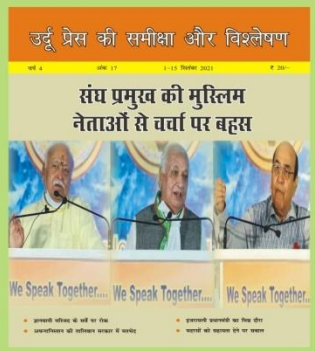

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in